THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) Running of 5-Star Hotels requires professional competence-managerial efficiency, experience in the trade, heavy investment involving loans advanced by public sector institutions. In view of this, the following conditions of eligibility have been prescribed by DDA:

(i) The Indian 5-Star Hoteliers having atleast one well-known established 5 Star Hotel/5-Star Delux Hotel with minimum annual turn over of Rs. 25 crores.

(ii) 5-Star Hoteliers who are foreign based should have at least 5 established 5-Star Hotels/5-Star Delux Hotels in different parts of the world.

(iii) Indian enterpreneurs who are having arrangement/collaboration with the Hoteliers satisfying conditions stipulated above in (i) and (ii) both.

(iv) Non-resident Indians who are willing to make investment in the country by arrangement/collaboration with the Hoteliers satisfying conditions stipulated above in (i) or (ii) or both. They would be required to remit foreign exchange for financing the project as required/permissible under the Rules.

Priority has also been given to 3/4 Star Hotels and Janata Hotels by earmarking 6 sites in various parts of the city. Interest subsidy of 3 per cent is also admissible on loan amount, subject to the prescribed conditions.

Tres-passing in reserved coaches

1329. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cases of tres-passing in reserved coaches have been on alarming increase causing murders of some foreign passengers in the past;

(b) whether Government propose to take some stern steps in this regard;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(d) whether any compensations have since been paid to the victims; and

(e) if so, the details thereof with criteria for payment of compensations?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Only one case of death of a French national due to a quarrel with daily commuters travelling in a reserved coach unauthorisedly has been reported last year.

(b) and (c) The following steps have been taken to prevent unauthorised entry in reserved coaches:—

(i) Surprise checks and drives are conducted from time to time with the help of GRP and unauthorised passengers found travelling in reserved coaches are detained and fined under the provisions of the Railways Act. Wherever the problem of unauthorised entry of passengers in reserved coaches is acute, coordination is established with GRP to enlist their assistance to prevent the same.

(ii) Punishments are imposed on Conductors/TTEs/Coach Attendants found responsible for dereliction of duty.

(iii) Distance restrictions on travel have been imposed in certain long distance trains.

(iv) Legal provisions in the new Railways Act, 1989, have been made more stringent in as much as a fine upto Rs. 500/- has been prescribed as against Rs. 20/- in the present Act.

(d) and (e) No claim for compensation has been preferred. An *ex-gratia* amount, Rs. 5,000/- was paid to the wife of the deceased French national.

1330. [*Transferred to the 28th March 1990*].

Headquarters reservation quota in trains

1331. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railway Board controls some HQR reservation quota; and

(b) if so, the details of the reservations provided through this quota in each class and in each train leaving Delhi/New Delhi from 12th February, to 18th February, 1990?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Emergency Quota in trains originating and passing through Delhi is controlled jointly by Railway Board and Northern Railways.

(b) A statement is attached. [*See* Appendix CLIII, Annexure No. 55].

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

1332. **श्री मिर्जा इर्शादबेग :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के पश्चात् चीनी, तेल, दालों और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है, इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ख) क्या सरकार एक रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है। जहां बाजरा, मक्का, जौ, अरहर, मूंग, जिंजली के तेल, सरसों के तेल, नारियल के तेल, मूंगफली के तेल और बिनौले के तेल जैसी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि दिखाई दी है, वहीं चावल, गेहूं, ज्वार, रागी, चना, मसूर, उड़द, चीनी, वनस्पति, करडी के तेल तथा चावल की भूसी के तेल जैसी अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें 25-11-89 तथा 3-3-90 की अवधि के बीच अनाजों, दालों, चीनी तथा खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांकों में आया उतार-चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाया गया है। (नीचे देखिए)

खाद्य तेलों तथा अनाजों के तहत कुछ वस्तुओं और दालों आदि के मूल्यों में वृद्धि के रुख का कारण मौसमजन्य कारणों, उत्पादन में कमी (अर्थात् खरीफ की मूंगफली) और उपभोक्ता मांग के दबाव आदि को माना जा सकता है।

मौजूदा सरकार ने मूल्यों में वृद्धि के रुख को रोकने को उच्चतम प्राथमिकता दी है। नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है, जो मूल्यों को नियंत्रित करने से संबंधित बातों को देखेंगी और चीनी तथा खाद्य तेलों पर विशेष ध्यान देगी। नागरिक पूर्ति विभाग भी राज्य सरकारों के जरिए चुनी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता की स्थिति की परिवीक्षा कर रहा है। जब कभी मूल्यों में किसी असामान्य वृद्धि अथवा कमी की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, उन्हें राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार में संबंधित विभागों के ध्यान में लाया जाता है और उनसे उपचारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया जाता है।

किए गए अन्य उपायों में मोटेतौर पर निम्नलिखित उपाय शामिल हैं : जिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम है उनके उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों तथा अन्य नियामक उपायों को सख्ती से लागू करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो, वहां आयात के जरिए देशीय आपूर्ति में वृद्धि करना, ताकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली किसी असामान्य वृद्धि को रोका जा सके।

(ख) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।